

## भारत सरकार Government of India पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय Ainistry of Environment, Forest & Climate Change क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ



Regional Office, Lucknow . केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No: 0522-2326696

Email: rocz.lko-mef@nic.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 : 8बी / यू0पी0 / 09 / 206 / 2022 / एफ.सी. /04

दिनांक : 07.04.2025

सेवा में

अति० मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

## ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/42798/2019

विषयः मे0 आई0एच0बी0 लि0 द्वारा काण्डला-गोरखपुर एलपीजी पाइप लाईन परियोजना (उन्नाव से गोरखपुर सेक्षन) के अन्तर्गत जनपद—उन्नाव में प्रभावित 1.284 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0069 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 617 वृक्षों / पौधों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.1295 है0 संरक्षित वनभूमि, प्रतापगढ़ में प्रभावित 0.0235 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों / पौधों के पातन, देवरिया में प्रभावित 0.0028 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों / पौधों के पातन, गोरखपुर में प्रमावित 0.05 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 32 वृक्षों / पौधों के पातन, मऊ में प्रभावित 0.004 हे0 संरक्षित वनभूमि जौनपुर में प्रभावित 0.008 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 06 वृक्षों / पौंघों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 0.6808 है0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0135 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1111 वृक्षों / पौधों के पातन, वाराणसी में प्रभावित 0.0046 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 02 वृक्षों / पौधों के पातन, लखनऊ में प्रमावित 1.738 हे0, आरक्षित वनभूमि एवं 0.035 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 2690 वृक्षों / पौधों के पातन अर्थात् 0.2778 है0 संरक्षित एवं 3.7028 है0 आरक्षित कुल 3.9806 है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4466 वृक्षों / पौघों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 2682/11-सी-FP/UP/Others/42798/2019, दिनांक 19.03.2025. महोदय.

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेष शासन के पत्रांक पी-244/81-2-2022-800(227)/2022, दिनांक 15.07.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.11.2022 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गई है। प्रस्तुत अनुपालना के परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार मे० आई०एच०बी० लि० द्वारा काण्डला-गोरखपुर एलपीजी पाइप लाईन परियोजना (उन्नाव से गोरखपुर सेक्षन) के अन्तर्गत जनपद-उन्नाव में प्रभावित 1.284 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0069 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 617 वृक्षों / पौधों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.1295 हे0 संरक्षित वनभूमि, प्रतापगढ़ में प्रभावित 0.0235 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों / पौधों के पातन, देवरिया में प्रभावित 0.0028 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों / पौघों के पातन, गोरखपुर में प्रभावित 0.05 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 32 वृक्षों / पौघों के पातन, मऊ में प्रभावित 0.004 है0 संरक्षित वनभूमि जौनपुर में प्रभावित 0.008 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 06 वृक्षों / पौंधों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 0.6808 है0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0135 है0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1111 वृक्षों / पौधों के पातन, वाराणसी में प्रभावित 0.0046 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 02 वृक्षों / पौधों के पातन, लखनऊ में प्रभावित 1.738 हे0, आरक्षित वनभूमि एवं 0.035 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 2690 वृक्षों / पौधों के पातन अर्थात् 0.2778 हे0 संरक्षित एवं 3.7028 हैं0 आरक्षित कुल 3.9806 हैं0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4466 वृक्षों / पौधों के पातन की विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करती है:-

- 1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in total area of 8.12 ha. in Bhadokhar Forest Block, Range & Distt.- Raibareilly (6 ha.) and in Khurhati Forest Block, Range & Distt.-Raibareilly (2.12 ha.), at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species shall be avoided.
- 3. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the
- 4. User agency shall restrict the felling of trees to 4466 trees/any minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and the State Forest Department shall undertake the fellings.

The pipeline shall be laid 1.5 meter below ground and after laying of cable ground shall be properly levelled.

- 6. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 7. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.
- 8. No labour camp shall be established on the forest land.
- 9. The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.
- 10. Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- 11. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 12. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 13. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
- 14. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 15. The KML file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
- 16. Annual 3rd party monitoring and concurrent internal monitoring by State Forest Department shall be done and monitoring reports submitted to this office.
- 17. The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the Court orders, provisions, rules, regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.
- 18. Project Completion Report and Stage-II compliance report shall be submitted within a period of 6 months of completion of project.
- 19. The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable for cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Adhiniyam or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.
- 20. Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, (1980), and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline.
- 21. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

भवदीया,

(विजया रात्रे)

सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

## प्रतिलिपि : (ई-मेल द्वारा)

- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
- 2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेषक, आजमगढ़, प्रयागराज एव वाराणसी।

4. प्रभागीय व्रनाधिकारी / निदेषक, उन्नाव प्रयागराज, प्रतापगढ़, देवरिया, गोरखपुर, मऊ, जौनपुर, रायबरेली, वाराणसी एवं लखन्छ।

 मुख्य परियोजना प्रबन्धक, आई०एस०बी० लि०, पहली मंजिल विष्वषील परिसर, बी-2/6, विभूतिखण्ड, लखन पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेष पत्रावली।

सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)